(d) and (e) The Government of India is also implementating a comprehensive project for the growth of the leather industry in India with the financial assistance from the UNDP. Besides, the Council for Leather Export is implementing sub-subjects which aim at enhancing export capabilities of the Members of the Council.

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को पुनः चालू किया जाना

2012. **श्री कामेश्वर पासवान :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग, कारपोरेशन रांची के पुनर्निर्माण संबंधी मामला औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास अंतिम अनुशंसा किए जाने के लिए लंबित पड़ा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रबन्धन स्टेट बैंक और सरकार द्वारा किए गए तदर्थ आर्थिक उपायों के कारण कारपोरेशन की स्थिति में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि उद्योग मंत्रालय द्वारा 31 अक्तूबर, 1993 तक कार्यान्वयन संबंधी पैकेज प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा अंतिम अनुशंसा नहीं की जा सकी; और

(घ) सरकार कारपोरेशन का पुनर्वास करने और इसे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही चलाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (एच० ई० सी०) घाटे वाली कंपनी होने के कारण, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को संदर्भित कर दी गई है।

(ख) एच० ई० सी० के निष्पादन में 1991-92 की तुलना में 1992-93 में सुधार हुआ है।

(ग) बी० आई० एफ० आर० से एक प्रचालन एजेन्सी नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है जो एच० ई० सी० द्वारा प्रस्तुत टर्न अराउन्ड योजना की जांच कर सके।

(घ) सरकार कम्पनी को योजना और गैर-योजना निधियां देकर, बैंकों में नकद जमा सीमा बढ़ा कर और बेशी श्रमशक्ति को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना द्वारा युक्तिपरक बनाने इत्यादि के द्वारा इसकी सहायता कर रही है।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को हुआ घाटा

2013. **श्री गया सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1993-94 के अक्तूबर माह तक हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, हटिया को कुल कितना घाटा हुआ है? **उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्यमंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही):** हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (एच० ई० सी०) को वर्ष 1993-94 में अक्तूबर तक 69.16 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

नई औद्योगिक नीति के अधीन स्थापित किए गए उद्योग

2014. **श्री गया सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति को लागू करने के बाद देश में अब तक स्थापित किए गए नए उद्योगों का ब्यौरा क्या है? **उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) :** जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद से नवंबर 1993 तक देश में विभिन्न उद्योगों की

स्थापना करने के लिये 11,973 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन फाइल किए गए थे। इनमें से नवबंर, 1993 के अंत तक 860 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों के संबंध में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ हो जाने की सूचना मिल गई है।

बिहार में नए उद्यमों की स्थापना

2015. **श्री गया सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में निकट भविष्य में नए सार्वजनिक और निजी उद्यमों को स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जाना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिकी विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबंधों के अधीन बिहार में विभिन्न उद्योग स्थापित करने के लिए वर्ष 1993 (नवम्बर तक) के दौरान 5 आशय पत्र दिए गए हैं। बिहार में उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस मुक्त क्षेत्र में वर्ष 1993 (नवम्बर तक) 36 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन भी प्रस्तुत किए गए थे।

(ख) और (ग) ये प्रस्ताव मुख्यतः धातु-कर्मी उद्योगों, ईंधन, वैद्युत व उपकरण, रसायन, वनस्पति तेल, परिवहन, उर्वरक और चीनी इत्यादि उद्योग के लिए हैं। धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, पटना, सिंहभूम, वैशाली, नालन्दा, बेगुसराय और पूर्वी चम्पारन इत्यादि जैसे जिलों को ज्यादा पसन्द किया गया है।

Shifting of office of the Salt Commissioner

2016. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the State Government of Gujarat has repeatedly represented for shifting of Office of the Salt Commissioner from Jaipur to Gandhinagar;

(b) whether it is also a fact that the State Government has offered to provide accommodation facility for this office and even bunglows and quarters for officers and staff at Gandhinagar; and

(c) if so, by when this office will be shifted to Gandhinagar ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPTT. OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SMT. KRISHNA SAHI) : (a) to (c) There has been demand from the State Government of Gujarat for shifting the office of Salt Commissioner from Jaipur to Gandhinagar. They have also offered an area of 1015 square metres as office space, two officer's bungalows and ten staff quarters in case it is decided to shift the office. There is, however, no proposal at present to shift the office to Gandhinagar.

Constraints faced by Indian Industries

2017. SHRI KRISHAN LAL SHARMA : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the industry of the country suffers from several constraints like continuing high cost of production, low productivity of labour force and recession;

(b) if so, whether Government have taken any action in this regard and if so, the details thereof and the results achieved; and

(c) what further steps Government propose to take in this regard ?